three cotton years (September—August) were as under:

Year	Average prices (in Rs/-)
1992-93	28.70
1993-94	43.82
1994-95	57.05

(b) and (c) Import of cotton is permitted unde OGL with zero import duty. There could be some import of cotton by mills, depending on their specific requirements and subject to comparative international prices.

विदेशी पूंजी निवेश

2253. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजी निवेश या इसके नकारात्मक प्रभाव की स्थिति के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन करवाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्र (डा० देवी प्रसाद पॉल): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान ने विदेशी पूंजी निवेश पर दो अध्ययन किए। प्रथम अध्ययन "विदेशी निवेश प्रस्ताव: एक विश्लेषण" (अगस्त, 1991—जुलाई, 1993) शीर्षक से मार्च, 1994 में प्रकाशित हुआ। दूसरा अध्ययन विदेशी निवेश प्रस्ताव और कार्यान्वयन स्थिति — एक समीक्षा (अगस्त, 1991—दिसम्बर, 1994 शीर्षक से मार्च, 1995 में प्रकाशित हुआ। अध्ययनों की प्रमुख टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

— विदेशी निवेश प्रस्तावों का परिमाण वितरण अत्यधिक विषम है।

— वर्ष 1991—94 के दौरान कुल एफ०डी०आई० प्रस्तावों में से, धनराशि का लगभग 3/4 भाग विकसित देशों द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें सं०रा०अ० ने इन देशों के निवेश के आधे भाग में भागीदारी की।

— विद्युत, तेल, लोहा और इस्पात, दूर-संचार, उपस्कर आदि जैसे क्षेत्रों में जो अब तक आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थे पश्च नीति अवधि के दौरान विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा निवेश हुआ।

— तकनीकी सहयोग में स्वचालित प्रक्रिया अधिक प्रभावी है।

— प्रस्तावों और निवेश धनराशियों दोनों क्षेत्रों में एफ०आई०पी०बी० के महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

— जनवरी तक 2177.4 करोड़ रुपए के लिए 743 स्वचालित प्रस्तावों में से 687.1 करोड़ रुपए के लिए 251 मामलों में वास्तविक अन्तः प्रवाह की सूचना प्राप्त हुई।

— अनेक उद्योगों में क्रमशः प्रगतिशील रूप से स्थानीय वायदा बाजार के खिलाड़ियों को हटाने के लिए प्रतिस्पर्धा बड़े टी० एन० सी० के बीच हो सकती है।

— उदार विदेशी निवेश नीति के अभाव में, विदेशी निवेशक शायद, इक्विटी स्टेक रखने और उद्यमों पर नियंत्रण रखने पर बल देते रहने की बजाए प्रौद्योगिकी को लाइसेंस प्रदान करने तक सहमत रहते।

— बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अन्य प्रमुख गतिविधियों के विपरीत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास घरेलु देशों तक सीमित करने हेतु प्रवृत्त होता है।

मुद्रास्फीति दर में वृद्धि

2254. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1995 के दैनिक आब्जर्वर में "सुपोर्ट प्राइसेज कौजेज आफ इनफ्लेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में खाद्यान्न की समर्थन कीमतों के कारण देश में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार के अनुमान के अनुसार खाद्यान्न की समर्थन कीमतों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद

(ख) और (ग) कृषि समर्थन/न्यूनतम समर्थन कीमतें एकमात्र खाद्यान्नों (मोटे अनाजों और दालों) के लिए ही नहीं बल्कि तेलहनों तथा कुछ अन्य कृषि-औद्योगिक निविष्टियों के लिए भी घोषित की जाती हैं। मुद्रास्फीतिकारी दबावों के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों में से पिछले चार वर्षों के दौरान कृषक समुदाय को दी गई न्यूनतम समर्थन कीमतों में वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला (आधारः 1981-82) के माध्यम से मानीटर की गई बाजार कीमतों पर उनके प्रभाव के रूप में एक महत्वपूर्ण कारक था। ये वस्तुएं उन वस्तु समूहों, जो श्रृंखला के अधीन प्राथमिक वस्तु होती है, के खाद्य पदार्थों और गैर-खाद्य पदार्थों के उप-समूह में शामिल की जाती हैं। खाद्य वस्तुओं में खाद्यान्न भी शामिल होते हैं।

मुख्य मोटे अनाजों और दालों के लिए सरकार द्वारा घोषित कृषि समर्थन कीमतें वर्ष 1992-93 में 16 प्रतिशत, 1993-94 में 6 प्रतिशत और 21 प्रतिशत के बीच और 1994-95 में 10 प्रतिशत तक थी। खाद्यान्नों की कीमतों में घट-बढ़ द्वारा थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में इसका अंशदान नीचे सूचीबद्ध है:

	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	खाद्यान्नों द्वारा अंशदान (प्रतिशत)
1993-94	10.8	13.0
1994-95	10.4	7.1
1995-96 नवम्बर, 1995 तक	8.0	4.8

विवेकाधीन कोष

2255. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मंत्री को विवेकाधीन कोष से कितनी धनराशि निकालने का प्रावधान था; और

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस कोष से प्रत्येक मंत्री द्वारा निकाली गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति): (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Shifting of Regional Office of State Bank of Bikaner & Jaipur

2256. SHRI ANIL KUMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that there is a proposal to shift the Regional Office of State Bank of Bikaner & Jaipur from Patna to Delhi;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any representation has been received by Government in this regard; and

(d) if so, the details of action taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BEBI PROSAD PAL): (a) and (b) State Bank of Bikaner and Jaipur has reported that it has received a proposal from its Zonal Office, Delhi, to shift Patna Regional Office to Zonal Office at Delhi for better control and expeditious disposal of credit proposals and other matters relating to customer service.

(c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Availability of Gas to Rewas/Mandwa Combined Cycle Gas Turbine Project

2257. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of POWER be pleased to state:—

(a) whether the Central Electricity Authority (CEA) has turned down the